ठोस पहल जरूरी

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर में कमी आयी है. कमजोर मॉनसून और देश के कई हिस्सों में जल संकट भी चिंताजनक संकेत दे रहे हैं. ऐसे में सरकार के सामने आर्थिक बढ़ोतरी को गति देने की बड़ी चुनौती है. वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर 5.8 फीसदी रही थी तथा पूरे साल का आंकड़ा सात फीसदी से भी घटकर 6.8 फीसदी के स्तर पर आ गया. इस अवधि में हर तिमाही में आर्थिक नरमी का रुझान रहा. इसके साथ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की चुनौती भी सामने है, जो कि श्रम शक्ति के हर भाग-कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल- में है. ये चिंताएं सरकार की प्राथमिकता में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दो कैबिनेट समितियों का गठन किया है. एक समिति निवेश और वृद्धि से संबद्ध होगी, जबकि दूसरी समिति रोजगार एवं कौशल विकास पर केंद्रित होगी. संभवतः यह पहला मौका है, जब इन मुद्दों पर कैबिनेट समितियां बनायी गयी हैं. इन दोनों समितियों की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे. इससे स्पष्ट इंगित होता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा रोजगार के समुचित अवसर पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय कर लिया है. आर्थिक नरमी का एक कारण निवेश में कमी है. वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में कुल फिक्स्ड पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पादन के 32.8 फीसदी के स्तर पर था, लेकिन चौथी तिमाही में यह घटकर 30.7 फीसदी हो गया. कृषि क्षेत्र में तो विकास दर पहली तिमाही के 5.1 फीसदी से गिर कर चौथी तिमाही में ऋणात्मक 0.1 फीसदी हो गयी. औद्योगिक उत्पादन में भी नकारात्मक संकेत हैं. ऐसे में अर्थव्यवस्था के हर महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है. बैंकों के संरचनात्मक पुनर्गठन तथा सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की योजनाओं पर गंभीरता से पहल करने की दरकार है. कृषि संकट से निबटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, पर मॉनसून की बारिश अगर पर्याप्त नहीं हुई, तो किसानों को राहत पहुंचाने तथा खाद्य उत्पादन कम होने की मुश्किलों के हल के लिए तैयारी की जानी चाहिए. अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिकी की उथल-पुथल से तेल और मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर भी नजर रखी जानी चाहिए. घरेलू बाजार में मांग घटने तथा निर्यात में अपेक्षित बढ़ोतरी न हो पाना भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है. मांग, उत्पादन और रोजगार के समीकरण पर ही आर्थिक वृद्धि निर्भर करती है. अनेक साहसी आर्थिक निर्णय लेना मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी. इससे आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक दायरे में लाने में कामयाबी मिली है तथा कराधान की प्रक्रिया सरल व प्रभावी हुई है. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट समितियां जल्दी ठोस सुधार व उपाय तय कर उन्हें अमल में लाने की कोशिश करेंगी.

मांग, उत्पादन और रोजगार पर ही आर्थिक वृद्धि निर्भर करती है. ऐसे में अर्थव्यवस्था के हर महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

बोधि वृक्ष

शिष्यत्व

समर्पण तनाव-मुक्ति का एकमात्र साधन है. सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देने से हमारा बोझ कम हो जाता है. सच तो यही है कि होनी हमारे वश में नहीं. इस ज्ञान के साथ हम अपने सभी कर्म कर, उन्हें ईश्वर को अर्पित कर दें, परंतु कर्तृत्व न लें. हमारा भाव यह रहे कि हम सब कर्म उसकी कृपा से कर रहे हैं. यही समर्पण का भाव हमें विकसित करना होगा. परमात्मा प्रतिक्षण हमें सरल, मधुर शब्दों द्वारा राह दिखलाता है, परंतु दुर्भाग्य, कि हम में सुनने का धैर्य ही नहीं, हम उसकी कही बात को सुनते ही नहीं. तभी तो हम बारंबार गलतियों को दोहराते रहते हैं और फिर दुख पाते हैं. हमें शिष्यत्व के एक आवश्यक गुण आज्ञा पालन को विकसित करना चाहिए. जब यह भाव जागृत हो जाता है, जब हम ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा तथा विनम्रतापूर्वक उसके शरणागत होते हैं, तब ही वह गुरु बन कर हमारा मार्गदर्शन करने का दायित्व लेता है. जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ. समर्पण की बात चले तो मन में राधा का विचार आता है. जब कृष्ण वृंदावन छोड़ कर मथुरा गये, तो वो राधा अथवा किसी गोपी को साथ नहीं ले गये थे. अतः वे सब अति-निराश हो गयीं. एक बार जब उद्धव मथुरा से आये तो राधा से मिल कर बोले कि, 'सभी गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने संदेश में पूछा है कि अब वह मथुरावासी ही हो जायेंगे अथवा उन्हें भी वहां बुला लेंगे? तुमने मुझे कृष्ण के लिए ऐसा कोई संदेश क्यों नहीं दिया? राधा ने उत्तर दिया, 'जब घर का स्वामी बाहर जाता है, तो या तो वह दास को साथ ले जाता है या नहीं ले जाता. यदि न ले जाए, तो इसमें दास क्या करता है? घर की चाकरी करते हुए स्वामी के लौट आने की प्रतीक्षा करता है. मैं कृष्ण की दासी हूं, अतः उन्हें अधिकार है कि मुझे साथ ले जाएं अथवा यहां छोड़ जाएं. मेरे हृदय में जो उनके प्रेम की ज्योति है, मैं उसे दुख से मंद नहीं पड़ने दूंगी. यही एक सच्चे भक्त का, दास का भाव है! इसी भाव के मध्यम से हम आत्मबोध की प्राप्ति कर सकते हैं.

श्री माता अमृतानंदमयी देवी

विचारहीन राजनीति का अवसान

भूपेंद्र यादव
सांसद, राज्यसभा व राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा
prabhatkhabardelhi@gmail.com

चुनाव परिणाम आने के बाद देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव पूर्व बना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन टूट गया. हालांकि, यह गठबंधन टिकने वाला नहीं है, इसको लेकर चुनाव से पहले ही सभी को अंदाजा था. चुनाव से पहले बेमेल की एकजुटता का राग अलापने वाले दलों के इस गठबंधन की नियति यही थी. हालांकि, साझा गठबंधन की हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी के माथे फोड़ते हुए गठबंधन से अलग होने का निर्णय बसपा ने एकतरफा लिया है. बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो का यह निर्णय दर्शाता है कि विपक्ष की राजनीति समाज में होनेवाले परिवर्तन के मूल मुद्दों और विचारों से भटक गयी है. विचारधारा की अस्पष्टता और दृष्टिकोण में असमानता के साथ जब राजनीतिक गठबंधन सिर्फ सत्ता के अवसरवाद में बनते हैं, तो उनका स्वाभाविक हश्र कुछ इसी तरह का होता है.

भारत की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करनेवाले नेताओं में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, डॉक्टर राममनोहर लोहिया और पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रमुख हैं. डॉ राममनोहर लोहिया ने राजनीति में सप्तक्रांति का विचार दिया. लोहिया द्वारा दिया गया सप्तक्रांति का विचार सामाजिक परिवर्तन एवं सुधारों के बुनियादी आवश्यकताओं को परिभाषित करनेवाले बिंदु की तरह है.

सप्तक्रांति की बात करते हुए डॉक्टर लोहिया ने लैंगिक भेदभाव से मुक्ति तथा स्त्री-पुरुष समानता की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने राजकीय, आर्थिक और मानसिक स्तर पर भेदभाव से मुक्त होने की जरूरत का विचार दिया है. सप्तक्रांति के विचारों में जन्मजात रूप से जातिगत पिछड़ापन को सामाजिक समस्या के रूप में चिह्नित करते हुए, इसके निराकरण की बात की गयी है. पैदावार बढ़ाने, पूंजीगत विषमता, आर्थिक असमानता आदि विषयों को डॉ राममनोहर लोहिया ने अपने विचारों में सही ढंग से रेखांकित किया है.

इन विचारों के जरिये लोहिया की दृष्टि समाज के वंचित और गरीब को न्याय दिला कर समाज और राजनीति की मुख्यधारा में शामिल करने की थी. किंतु वर्तमान में लोहिया और आंबेडकर के नाम पर राजनीति करनेवाले ऐसे अवसरवादी राजनीतिक दलों का आचरण उनके विचारों से ठीक उलट है. यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया की वैचारिक विरासत तो दूर, अपने पिता की राजनीतिक विरासत को भी नहीं सहेज पाये. राजनीति की जो धारा सामाजिक न्याय के उद्देश्य से चली थी, सपा के वर्तमान अध्यक्ष ने उसे संकीर्ण राजनीति का रूप देकर अपने दल का भी नुकसान किया, अपने समाज का भी नुकसान किया और देश की राजनीति में डॉ राम मनोहर लोहिया जी के विचारों का तो सबसे बड़ा नुकसान किया ही.

यह भी सच है कि राजनीति को केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार के सत्ता हितों का साधन बनाकर एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत अब देश की जनता नहीं देने वाली.

राजनीति करते समय हमें महात्मा गांधी की उस ताबीज को याद करना चाहिए, जो उन्होंने 'सत्तर साल' पहले दी थी, 'जब भी कोई निर्णय लो, तो समाज के अंतिम व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है, यह सोच कर निर्णय करो.'

महागठबंधन में हुए हालिया घटनाक्रमों में निहित राजनीति ने सिद्ध किया है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने खुद को एक जातिवादी अहंकार में कैद कर लिया था और अभी भी वे उस अहंकार से खुद को उबार नहीं पा रही हैं. बाबा साहब आंबेडकर ने उच्च नैतिकता का चुनाव करते हुए सार्वजनिक जीवन जिया, जिसे बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने कभी नहीं अपनाया. मैं मानता हूं कि अनुसूचित जाति के समाज की जो बड़ी समस्याएं हैं, उनसे जुड़ा जो चिंतन है, युवाओं की आकांक्षाएं हैं, उसको भी दरकिनार करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के कारण किया है.

एक बात और गौर करनी होगी कि चुनाव परिणामों का सटीक आकलन कर पाने में अनेक राजनीतिक विश्लेषक इसलिए चूक गये, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव को गठबंधनों के वोट ट्रांसफर का चुनाव मान कर आकलन किया, जबकि यह चुनाव वोट ट्रांसफर का चुनाव नहीं था, यह नये भारत के निर्माण का चुनाव था. जब केंद्र में कोई सरकार बनती है अथवा केंद्र का चुनाव होता है, तो देश की सुरक्षा, विदेशनीति, अर्थनीति जैसे मूल मुद्दों पर किसी भी दल का राजनीतिक चिंतन उभर कर आना चाहिए. विपक्ष ऐसे किसी भी चिंतन को रखने का प्रयास करता भी नहीं दिखा. इसमें कोई संदेह नहीं कि विचारधारा विहीन और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से विमुख होकर अगर राजनीति को हमने महज वोट ट्रांसफर के चुनाव में तब्दील कर लिया, तो ये राष्ट्र की नहीं बल्कि कबीलों की राजनीति बनकर रह जायेगी. लेकिन, एक स्वस्थ एवं परिपक्व लोकतंत्र के रूप में देश ने डॉ राममनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर और दीन दयाल उपाध्याय जैसे विचारकों के चिंतन के अनुरूप गरीब आदमी को ताकत देने की राजनीति को इस देश ने स्वीकार किया है. यह भारत के लोकतंत्र के लिए उत्कर्ष का विषय है.

वैसे बेमेल गठबंधन में हाल तक रहे राजनीतिक दलों की बौखलाहट से किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों को सम्मान से जीवन जीने का मार्ग दिखाया है और लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है. लोग अपनी सहज सामाजिक परंपरा, अपनी वेशभूषा, खान-पान और रहन-सहन जैसी चीजों के साथ नये भारत की आकांक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यह रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है.

वहीं, विपक्षी राजनीतिक दलों की बिखराव की राजनीति यह दिखाती है कि भारत की जनता द्वारा नकारी गयी ताकतें अपना वोट ट्रांसफर न होने से हताश हैं. हर गरीब भी अब भारत निर्माण में अपनी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है.

राजनीति करते समय हमें महात्मा गांधी की उस ताबीज को याद करना चाहिए, जो उन्होंने देश की दिशा देते हुए की 'सत्तर साल पहले दी थी, 'जब भी कोई निर्णय लो, तो समाज के अंतिम व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है, ये सोच कर निर्णय करो.'

विश्व सिनेमा का बदलता भूगोल

अजित राय
फिल्म विश्लेषक
ajitraieditor@gmail.com

कान का फिल्म बाजार इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार बन चुका है, जहां 31,819 फिल्म कंपनियां पंजीकृत हैं. इस बार 114 देशों के 12 हजार एजेंट फिल्मों की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचे.

विश्व सिनेमा में कभी यूरोप-अमेरिका की तूती बोलती थी, पर अब यह भूगोल बदल गया है. अब एशिया और अफ्रीका की फिल्मों ने केंद्रीय जगह बना ली है. कान, बर्लिन, वेनिस जैसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में इन्हें पुरस्कार मिल रहे हैं. दुनिया के सबसे अहम कान फिल्म समारोह में भी यही देखने को मिला. पेद्रो अलमोदोवार, केन लोच, टेरेंस मलिक, क्वेंतिन तारंतीनो, मार्को बेलोचियो, जिम जारमुश, जेवियर दोलान, अब्दुल लतीफ केचीचे जैसे दिग्गज यूरो-अमेरिकी फिल्मकारों को पछाड़ कर इस बार दक्षिण कोरिया के बोंग जून हो ने फिल्म 'पारासाइट' के लिए बेहतरीन फिल्म का पुरस्कार जीत कर लगातार दूसरे साल एशिया का परचम लहराया है. पिछले साल जापान के कोरे इडा हिरोकाजू को 'शॉपलिफ्टर' के लिए यह सम्मान मिला था. संयोग से इन दोनों फिल्मकारों की विषय-वस्तु एक ही है- एशिया के दो सबसे अमीर देशों में पसरती गरीबी. कान फिल्म समारोह के इतिहास में फ्रेंच-सेनेगल की मैती दिओप पहली अश्वेत महिला फिल्मकार हैं, जिन्हें इस बार 'अटलांटिक्स' के लिए दूसरे सबसे खास पुरस्कार 'ग्रैंड पिक्स' से नवाजा गया है. यह फिल्म सेनेगल में प्रवासी मजदूरों की जिंदगी और सेक्स की राजनीति पर आधारित है.

इस समारोह में निर्णायक मंडल के प्रमुख अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितू द्वारा घोषित लगभग सभी पुरस्कार नये फिल्मकारों को मिले हैं. इनमें मैती दिओप के अलावा बेल्जियम के ज्यां पियरे और लुक दारदेन बंधु उल्लेखनीय हैं. फिलीस्तीन के एलिया सुलेमान की फिल्म 'इट मस्ट बी हेवन' का विशेष उल्लेख हुआ है. इस फिल्म में सुलेमान पेरिस से न्यूयॉर्क तक का चक्कर लगाते हुए यह जानने की कोशिश की है कि दुनिया में वह कौन-सी जगह है, जिसे सचमुच में हम अपना घर (मातृभूमि) कह सकते हैं.

कान फिल्म समारोह के इतिहास में पहली बार इस आयोजन में मैक्सिको के किसी फिल्मकार को जूरी का अध्यक्ष बनाया गया था. यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया के दौर में लेबनान की नदिन लाबाकी को 'अनसर्टेन रिगार्ड' खंड के निर्णायक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था. साल 1979 में कंबोडिया में हुए भीषण जनसंहार से किसी तरह बचकर पेरिस में शरणार्थी का जीवन जी रहे रिथि पांह 'कैमरा डि ओर' की जूरी का मुखिया बने थे. हॉलीवुड की दैत्याकार संरचना को अपनी फिल्मों से चुनौती देनेवाले और अमेरिका में इंडिपेंडेंट सिनेमा आंदोलन के अगुवा जिम जारमुश की फंतासी 'डेड डोंट डाइ' के प्रदर्शन से 72वें कान फिल्म समारोह की शुरुआत हुई थी. इन संकेतों से मतलब यह है कि यह प्रतिष्ठित आयोजन सिनेमा की समानांतर राजनीति को समर्थन दे रहा है. समारोह के निर्देशक थेरी फ्रेमो ने पिछले महीने ही पेरिस में घोषणा कर दी थी कि इस बार 'रोमांस और राजनीति' समारोह के मुख्य विषय होंगे. पिछले कुछ सालों की चर्चित फिल्मों से इंगित होता है कि वर्तमान विश्व सिनेमा मनुष्य की स्वतंत्रता का घोषणापत्र है. यह स्वतंत्रता बिना राजनीति के संभव ही नहीं है. रोमांस की अवधारणा भी औरत-मर्द के रिश्ते की हदों से आगे निकल चुकी है. एक प्रभावी कला माध्यम के बतौर सिनेमा से रोमांस के बिना कोई विशिष्ट फिल्म बन ही नहीं सकती है. और, इसके लिए भी स्वतंत्रता और राजनीति आवश्यक हैं.

कान समारोह की जूरी के अध्यक्ष इनारितू ने रेखांकित किया है कि आज दुनियाभर में लोकतंत्र गायब हो रहा है, पर सिनेमा में लोकतंत्र कायम है. उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संकट के कारण आज दुनिया संकट में है और हमारे राजनेता गुस्से, झूठ व आक्रोश के साथ शासन कर रहे हैं. इस फिल्मकार को भरोसा है कि सिनेमा का लोकतंत्र ही हमारी सभ्यता को बचायेगा. इस समारोह की सबसे बड़ी घटना प्रतियोगिता खंड में क्वेंतिन तारंतीनो की फिल्म 'वंस अपान ए टाइम इन हॉलीवुड' का प्रदर्शन और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभानेवाले दो सुपरस्टारों- लियोनार्दो डीकैप्रियो एवं ब्रैड पिट- की भागीदारी रही. 'पल्प फिक्शन' (1994) के लिए बेहतरीन फिल्म का पुरस्कार जीतने के 25 साल बाद वे इस नयी फिल्म के साथ समारोह में लौटे थे. बकौल तारंतीनो, 'मेरी फिल्म इंडस्ट्री को यह फिल्म मेरा प्रेम पत्र है.'

कान फिल्म समारोह में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन और अभिनेत्रियों के रेड कार्पेट पर चलने की फरेबी खबरों के बीच हमें इस सच्चाई को समझने की जरूरत है कि इस बार ऑफिशियल सेलेक्शन में एक भी भारतीय फिल्म नहीं थी. किसी भारतीय कलाकार को आधिकारिक रूप से कोई रेड कार्पेट वेलकम नहीं दिया गया था. यहां तक कि समारोह की समानांतर गतिविधियों- डाइरेक्टर्स फोर्टनाइट और क्रिटीक्स वीक- में भी कोई भारतीय फिल्म नहीं थी. फिर भी, भारतीय पवेलियन में चहल-पहल थी. इससे एक फायदा हुआ है कि भारतीय फिल्मकारों को नेटवर्किंग की सुविधा मिल जाती है और फिल्म बाजार तक पहुंच में मदद मिलती है. कान का फिल्म बाजार इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार बन चुका है, जहां 31,819 फिल्म कंपनियां पंजीकृत हैं. इस बार 114 देशों के 12 हजार एजेंट फिल्मों की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचे थे. फिल्मों और बाजार के जरिये भारतीय सिनेमा को कान से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए.

आपके पत्र

शहरीकरण से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या

हमने पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया. विश्व भर में बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग का कारण सिर्फ पेड़ों की कटाई अथवा प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल नहीं है. झारखंड, असम और मध्यप्रदेश में वनों की संख्या देश में ज्यादा है, बावजूद वहां भी ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है. गांवों की जमीन को बेचकर शहरों की तरफ पलायन, आबादी वृद्धि और कारों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि, दाढ़ी बनाने की क्रीम, लिपस्टिक और सुंदरता बढ़ाने के क्रीम का रसायन, गगनचुंबी इमारतें, गड्ढे और पोखरों को भरकर इमारत खड़ा करना, एसी कार और इमारत, सभी धर्मस्थलों में बजते लाउडस्पीकर, शहरों में कचरा प्रबंधन का अभाव इत्यादि भी ग्लोबल वार्मिंग के कारक हैं. ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना होगा.

प्रो सदानंद पॉल, नवाबगंज, मनिहारी (कटिहार)

मजबूत इच्छाशक्ति हो, तो दिव्यांगता नहीं बनेगी बाधा

कामयाबी पाने के लिए मजबूत शरीर नहीं, मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है. अगर हमारे हौसले बुलंद हों और इरादे चट्टान की तरह, तो दुनिया की हर बाधा पार की जा सकती है. मानसिक सुदृढ़ता के आगे शारीरिक कमी बौनी हो जाती है और लक्ष्य आसान हो जाता है. हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं, जिससे हम सीख ले सकते हैं. जैसे, बिहार की अरुणिमा सिन्हा ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपने पांव गवां दिये थे. लेकिन, उन्होंने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर यह साबित कर दिया कि अपंगता शरीर में नहीं दिमाग होती है. उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अपनी शारीरिक अक्षमता के आगे घुटने टेक देते हैं.

मोनू कुमार, छात्र, पटना कॉलेज (पटना)

स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करे सरकार

जिस राज्य को शिक्षा का केंद्र समझा जाता था, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थान पूरे विश्व में विख्यात थे, आज उसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, जो कि चिंता का विषय है. पूरे बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है. लगभग दो लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है. राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बिहार सरकार को संपूर्ण रिक्त पदों पर जल्द से जल्द बहाली शुरू करनी चाहिए, ताकि छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

प्रीतम राजू, कौआकोल (नवादा)

कुछ अलग

सेब के मुकाबिल केला

सुरेश कांत
वरिष्ठ व्यंग्यकार
drsureshkant@gmail.com

भले ही आम फलों का राजा हो, पर स्वास्थ्य के मामले में जो लोकप्रियता सेब की है, वह आम की नहीं. लगता है, उसने अपनी बिक्री बढ़ाने का काम किसी विज्ञापन-एजेंसी को दिया था. एजेंसी ने पहला काम किया, एक बढ़िया नारा बनाने का, क्योंकि नारा है तो सब-कुछ है. नारा भी बनाया अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी भी तो सब-कुछ है. लोग तो उसके पीछे अपनी मातृभाषा भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं और दूसरे की भी, बल्कि दूसरे की कुर्बान करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, भले ही इस चक्कर में अपनी भी कुर्बान हो जाये. अंग्रेजी में स्लोगन बना- 'एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे.' इस स्लोगन ने चमत्कार किया. परिणाम यह हुआ कि सुबह नाश्ते की मेज पर बाकी सारे फल पड़े के पड़े रह जाते हैं, लोग सेब पर ही हाथ साफ करते हैं. पपीता तो बीमारों के फल के रूप में बदनाम है ही, अंगूर भी सेब के सामने कहीं नहीं टिकता. रहा केला, तो जैसे स्त्री दलितों में भी दलित है, केला उपेक्षितों में भी उपेक्षित रहा. लेकिन वही केला अब सेब से टक्कर लेने की तैयारी में दिखता है. ताजा शोध यह है- दो केले खाइए, रक्तचाप और तनाव भगाइए. जरूर केले ने भी किसी विज्ञापन-एजेंसी का सहारा लिया है, वरना ऐसा मर्मस्पर्शी नारा न बनता. यह तो दुखती राग पर हाथ रखने जैसा हो गया. जैसी कि परंपरा है, पहले चूहों पर केले का असर परखा गया. चूहे वैसे कितने भी खुराफाती हों, इस मामले में मानवता के खूब काम आते हैं. पता चला, केला खाने से चूहों का रक्तचाप कम हो गया. पके हुए केले का असर ज्यादा होता है. फिर ऐसे ही प्रयोग रक्तचाप के रोगी मनुष्यों पर किये गये. अंततः निश्चित हो गया कि केले से रक्तचाप दूर होने के मामले में मनुष्य भी चूहों से कम नहीं हैं, तो इसकी घोषणा कर दी गयी. लगता है ये शोधकर्ता दवाओं के कारोबार में अरबों-खरबों रुपये की संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बर्बाद करने पर तुले हैं. केला रक्तचाप और तनाव दूर कर देगा, तो इन बीमारियों की महंगी-महंगी दवाएं बेचनेवाली कंपनियों का क्या होगा? भला केला फल है या दवाई? पर नहीं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूं. ताज्जुब नहीं होगा, अगर जल्दी ही किसी दिन किसी पश्चिमी देश की किसी लेबोरेटरी द्वारा प्रसारित यह खबर सुनने में आ जाये कि केला खाने से व्यक्ति एचआइवी पॉजिटिव यानी एड्स का शिकार हो जाता है. ये दवा कंपनियां ऐसे भारतीय शोधों से डरने वाली नहीं हैं, बल्कि हो सकता है, कल वे केले का पेटेंट ही अपने नाम करवा लें और हम उनके दावों की काट में अपने पुराने ग्रंथों के उन साहित्यिक उद्धरणों का हवाला देते ही रह जाएं, जिनमें नायिकाओं की जांघों की उपमा कदली वृक्ष के तनों से दी गयी है. और क्या पता, वे कंपनियां नीम और लहसुन की तरह केले के भी कैप्सूल बाजार में उतार दें! जो भी हो, वे कुछ करेंगी जरूर. भारतीय बाजार की उन्हें बड़ी चिंता है. उस चिंता से ही उनकी तिजोरियां भरती हैं.

देश दुनिया से

सूडान में प्रदर्शनकारियों पर नृशंसता

खार्तूम की सड़कों पर 60 सूडानी प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद, यहां सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जायेगा, क्योंकि यह देश नागरिक शासन स्थापित करने के लिए पहले से संघर्षरत है. बीते अप्रैल में विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बशीर को सत्ताच्युत करने के साथ ही विपक्षी लोकतांत्रित कार्यकर्ताओं में आशा जगी थी. हालिया हत्या से यह साफ हो जाता है कि बशीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो लाभ प्राप्त हुआ था, वह खून से लथपथ हो रहा है. मिलिशिया ग्रुप के इसमें शामिल होने से मृतकों की संख्या बढ़ रही है. यह ग्रुप सेना का हिस्सा था और सड़कों पर घूम कर निर्दोषों को गोली मार रहा था. जांजावीड मिलिशया, जो दार्फुल में नृशंसता के लिए जिम्मेदार था, अर्धसैनिक इकाई इन मौतों के लिए जिम्मेदार है. असल में यह विपक्षियों को आतंकित करने की योजना है, ताकि वे सत्ता पक्ष की शर्तों को स्वीकार कर लें. हत्याओं को लेकर हंगामा होने के बाद ट्रांजिशनल मिलिटरी कौंसिल ने नौ महीने में चुनाव कराने की घोषणा की. हालांकि, उकसावे और हत्याओं के बावजूद, लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी अहिंसक रहे हैं. इन प्रदर्शनकारियों का लक्ष्य है लोकतंत्र, चुनाव और लोकप्रिय जनादेश का शासन, न कि सैन्य शासन.

कार्टून कोना

साभार : कार्टून मूवमेंट